Springboard ACADEMY

भारतीय अर्थव्यवस्था

राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नोट्स

(RPSC के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार)

AN INSTITUTE FOR IAS & RAS
Plot A-1, Keshav Vihar, Riddhi Siddhi Chouraha, Gopalpura Bye Pass Jaipur
M.No. : 9636977490, 8955577492, Website : www.springboardindia.org

विषय सूची

Topic	Page
1 अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय	1
2 मांग एवं आपूर्ति	2
3 मौद्रिक नीति	6-15
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया	9
4 गैर लाभकारी परिसम्पत्तियां	16
5 मुद्रा आपूर्ति	20
सूक्ष्म वित्तयन	22
6 वित्तीय समावेशन	24
7 पूँजी बाजार	30
SEBI	37
8 कमोडिटी एक्सचेंज	39
9 मुद्रा स्फीति	41
10 राजकोषीय नीति	48
वस्तु एवं सेवा कर	52
11 बजट	58
12 राष्ट्रीय आय	67
मानव विकास सूचकांक	72
13 व्यापार नीति	77
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	80
सेज SEZ	85
14 विनीमय दर	90
15 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं	94
विश्व व्यापार संगठन	100
क्षेत्रीय व्यापार समझौते	106
16 गरीबी	109
17 कृषि	116
कृषि विपणन	129

अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय

फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई । रूसो नाम के व्यक्ति ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट (सामाजिक समझौता) लिखी ।

रूसो ने स्वतंत्रता, समानता व बंधुता को मुख्य रूप से प्रतिपादित किया ।

समानता	पूँजीवाद
(समाज, साम्यवादी)	(व्यक्ति, स्वतंत्रता)

रूस – 1917 समानता से पूँजीवाद 1991

चीन – 1949 1979

उ. कोरिया – 1950

– भारत 1991 में पूँजीवाद बना

Springboard ACADEMY

DEMAND – SUPPLY

मांग एवं आपूर्ति

मांग Demand (मुद्रा) = आपूर्ती Supply (उत्पादन)

Demand > SupplyDemand < Supply

⇩ ⇩

Inflation(मुद्रास्फिति)Deflation

(महंगाई) (आर्थिक मंदी)

⇩ ⇩

Monetary PolicyFiscal Policy

(मौद्रिक नीति) (राजकोषीय नीति)

– महंगाई से निपटने के लिए रिजर्व बैंक मौद्रिक निति को अपनाता है
– आर्थिक मंदी से निपटने के लिए रिजर्व बैंक राजकोषीय निति को अपनाता है

उत्पादन के क्षेत्र(Sectors of production)–

1. प्राथमिक क्षेत्र – कृषि(Primary Sector)
2. द्वितीयक क्षेत्र – औद्योगिक क्षेत्र(Secondary Sector)
3. तृतीयक क्षेत्र– सेवा क्षेत्र(Tertiary Sector)
4. चतुर्थ क्षेत्र– उच्च शिक्षा, अनुसंधान, सांस्कृतिक गतिविधियां(Quaternary Sector)
5. पंचम क्षेत्र – P.M. Ministers, President, CEOs (Pvt. Company)(Quainary Sector)

1. प्राथमिक क्षेत्र– प्राकृतिक संसाधनों से जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है/किया जाता हैं, उन्हें प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। जैसे– कृषि, पशुपालन, मत्सय पालन, वन उत्पादन, खनन आदि।

GDP में Primary Sector 17% योगदान करता है।

2द्वितीयक क्षेत्र.–विनिर्माण एवं निर्माण को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाताहै। खनन तथा बनने वाले द्वितीयक उत्पादों को द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है।जेसे: उघोगों मै वस्तु का निर्माण - ए.सी, कार पंखा आदि

निर्माण: भवन, सड़क आदि

GDP में Secondary Sector 28% योगदान करता है।

3. तृतीयक क्षेत्र– इस क्षेत्र में विभिन्न सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे–यातायात, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल etc.

GDP में इस क्षेत्र का योगदान -58% है।

4. चतुर्थ क्षेत्र– भौतिक सेवाओं को इस क्षेत्र में रखा गया है। जैसे– उच्च शिक्षा, अनुसंधान, सांस्कृतिक गतिविधियां सेवाएं

5. पंचम क्षेत्र–कुछ स्तरीय राजनितिक और आर्थिक निर्णय से सम्बंधित सेवाए. जैसे:– राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, CEO (निजी कंपनी), निर्देशक विभाग के CEO

भारत में खनन एवं विद्युत आपूर्ति को द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है ।

उत्पादन के साधन :–

साधन		साधन लागत
1. भूमि(Land)		किराया(Rent)
2. श्रम	(Labour)	मजदूरी(Wages)
3. पूंजी	(Capital)	ब्याज(Interest)
4. उद्यमी	(Enterpreuneur)	लाभ(Profit)

Q. भारतीय अर्थव्यवस्था में Primary Sector से Secondary sector को छोड़कर सीधे Teritary Sector का विकास कैसे हुआ ?

मांग का नियम :–

1. वस्तु की कीमत एवं उसकी मांग में नकारात्मक संबंध है।
2. कीमत एवं आपूर्ति में सकारात्मक संबंध है।

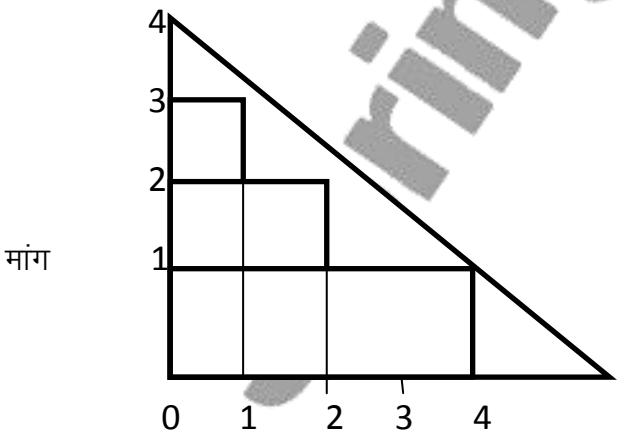

3. जहां क्रेता एवं विक्रेता दोनों संतुष्ट होते हो वहां वस्तु की कीमत तय होते है।

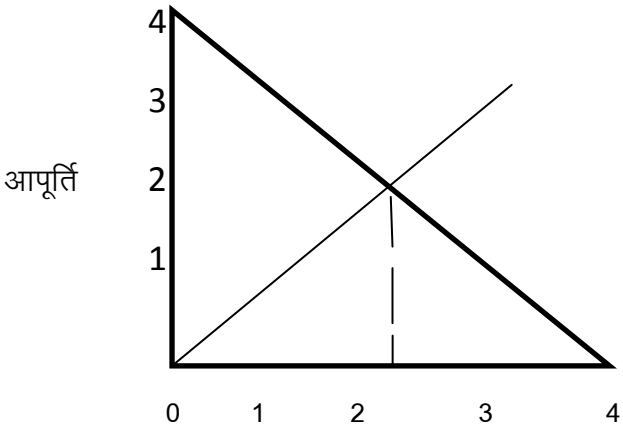

अपवाद :–

1.बुनियादी आवश्यकताओं की वस्तुओं पर यह नियम काम नहीं करता है। उदा.– नमक, क्रूड तेल, कच्चा तेल।

2. गिफ्फिन गुड्स:- जब किमतें बढ़ती है तो घटियां वस्तुओं की भी कीमत बढ़ जाती है/तथा उनकी मांग बढ़ जाती है।

3. Veblen Goods :- वे वस्तुएं जो सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हो उसकी कीमत अधिक होती हैउनकी मांग बढ़ जाती है।

4. फैशन गुड्स- जिन वस्तुओं का बाजार में चलन है/फैशन हो तो उनकी कीमत बढ़ेगी।

– मौद्रिक नीति :– 1. बैंकिंग
2. शेयर बाजार
3. मुद्रा स्फीति

– राजकोषीय नीति – 1. बजट – करारोपण → VAT – Value Added Tax
→ GST – Goods & Services Tax
2. घोट – 1. राजकोषीय घाटा
2. राजस्व घाटा
3. प्राथमिक घाटात्र
3. करारोपण

व्यापार नीति :– 1. BOP (भुगतान संतुलन)
2. BOP (संकट)
3. विदेश नीति निवेश
4. आयात निर्यात को प्रोत्साहन

Springboard ACADEMY

5. SEZ

6. विनीमय दर

7. रूपए की पूर्ण परिवर्तनीयता

8. अन्तराष्ट्रीय संस्था – विश्व बैंक

–IMF

–WTO

आर्थिक संवृद्धि – राष्ट्रीय आय – GDP

GNP

GVA etc.

आर्थिक विकास – HDR

HDI

IHDI

GII

NPI

GDI

– गरीबी एवं बेरोजगारी–सापेक्ष

निरपेक्ष

– उद्योग

– कृषि

–आयोजन

– पंचवर्षीय योजनाएं

Springboard ACADEMY

मौद्रिक नीति

1770 ई. मे बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था

– 1881 ई अवध कमशिर्यल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था.

– 1894 ई पंजाब नेशनल बैंक पहला भारतीए बैंक था

–SBI का इतिहास

बैंक ऑफ बंगाल 1806
बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 } प्रेजीडेंन्सी बैंक
बैंक ऑफ मद्रास 1843

- 1921 ई मे उपयुक्त तीन बैंक का विलय करके इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया.
- 1955 ई में इनका आंशिक राष्ट्रिय करण कर दिया गया और नया नाम SBI दिया गया
- 1959 ई रियासती बैंकों को SBI सहायक बैंक बना दिया गया
- 1961 ई बीकानेर व् जयपुर बैंक को मिला दिया गया– SBBJ
- 2008 मे स्टेट बैंक ऑफ सोराष्ट्र का SBI मे विलय कर दिया गया

(SBBJ, SBM, SBT, SBH, SBP)

- 2010 ई मे बैंक ऑफ इंदौर को SBI मे विलय कर दिया गया
- 2008 मे SBI को भारत सरकार ने RBI से खरीद लिया

RBI —
- IDBI – 1996
- SBI – 2008
- NABARD – 2010
- NHB – National Housing Bank
- DICGC

➢ राष्ट्रीयकृत बैंक

- 1969 मे इंदिरा गाँधी सरकार ने 14 सबसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीय करण कर दिया . जिनकी पूंजी 50करोड़ या इससे अधिक थी
- 1980 मे 6 अन्य बैंकों का इंदिरा गाँधी सरकार ने राष्ट्रीय करण किया जिनकी पूंजी 200 करोड़ या इससे अधिक थी
- 1993 मे न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय PNB मे किया गया.

Springboard ACADEMY

– वर्तमान मै राष्ट्रीयकृत बैंक 19 है
– NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की इस्थापना 1982 मे हुई

➢ सहकरिता बैंक

वाणीजिय्कबैंक	सहकारी बैंक
संसदीय अधिनियम के द्वारा स्थापना होती है	राज्य विधानसभा के द्वारा पारित अधिनियम से स्थापना
यह बैंक एक स्तरीय ढाचा होता है	त्रिक्तरिय ढ़ाचा होता है 1राज्य स्तर– APEX BANK 2 जिला स्तर – केंद्रीय बैंक 3 ग्राम पंचायत – सहकारी समिति
इनका कार्यक्षेत्र निधारित नही होता	इनका कार्यक्षेत्र निर्धारित होता है
शीर्ष संस्था RBI है	इनकी शीर्ष संस्था नाबार्ड है

➢ अनुसूचित बैंक
– वह बैंक जिनका उल्लेख RBI अधिनियम 1934 दूसरी अनुसूची मे किया गया है
– अनुसूचित बैंक चैक बुक जारी कर सकता है
– RBI से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता ले सकता है
– RBI के सभी नियमों का पालन होता है
– इस बैंक को स्थापित करने के लिए 500 करोड़ की पूंजी आवश्यक है

➢ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) रीजनल रूरल बैंक
– इनकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई
– इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों मे बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना है
– केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार व् वाणीजिय्क बैंक की सहायता से स्थापना होती है
– हिस्सेदारी वर्तमान प्रारंभिक
– गोवा व् सिक्किम में एक –एक बैंक की स्थापना की गई

– कुल पांच RRB – 1. मुरादाबाद (U.P.)
2. मालबा(M.P.)
3. भीवानी (हरियाणा)
4. जयपुर (Raj.)
5. गोरखपुर (UP)

– कालान्तर में ''200 RRB'' की स्थापना हुई।

– सिक्किम व गोवा में RRB नहीं है।

– इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है।

– लेकिन अधिकांश RRB घाटे में चल रही थी अतः इनका विलय ''कमर्शियल बैंकों'' में कर दिया।

यूनिवर्सल बैंकिंग – वह बैंक जो अपने ग्राहकों को वित्तीय सहायता के अलावा भी अन्य सहायता उपलब्ध करवाती हो जैसे – विपणन, तकनिकी, प्रबंधन क्षेत्र आदि

नैरो बैंक – ऐसा बैंक जो केवल सुरक्षित क्षेत्र में ही निवेश करता हो, उसे RBI की मान्यता प्रदान करना।

Springboard ACADEMY

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(RBI)

– 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना प्रारंभ किया।

– इसकी स्थापना RBI अधिनियम 1934 मे की गई

– इसकी स्थापना यंगहिलटन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 में भी केन्द्रीय बैंक स्थापना का प्रावधान है।

– स्थापना के समय से ही यह केन्द्रीय बैंक था और साथ ही एक प्राइवेट बैंक भी था।

–स्थापना के समय निजी क्षेत्र का बैंक था

– ''1 जनवरी 1949'' को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

– कुछ समय के लिए इसने बर्मा म्यांमार व पाकिस्तान की भी केन्द्रीय बैंक के रूप में काम किया।

➢ (RBI के मुख्य कार्य) :-

1. नोटों का निर्गमन करना।

   – RBI 2 रूपए से अधिक मूल्य के नोट जारी करता है।
     - 1 रूपए का नोट व सिक्का वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये जाते है।
   – लेकिन बाजार में इन्हें लाने का काम RBI का होता है।
   – न्यूनतम आरक्षित पद्धति के तहत RBI नोट जारी करता है इसके तहत 200 करोड़ की पूंजी आरक्षित रखनी होती है। इसमें 115 करोड़ का सोना तथा 85 करोड़ की विदेशी परिसम्पतियां रखनी होती है।
   – आनुपातिक आरक्षित पद्धति अपनाई जाती थी
   – न्यूनतम आरक्षित पद्धति (1956 में अपनाया था)

2. यह विनीयामक संस्था है।

3. बैंकिंग क्षत्रो के लिए यह नियम व विनिमय बनाती है और इन्हें लागू कराती है।

   – यह बैकों को निर्देश देती है।

4. भारत सरकार के लिए सभी प्रकार के ऋणों की व्यवस्था करता है और भारत सरकार के बैंकर के रूप मै कार्य करता है.

   – 2008 मे DMO (Debt Management Office) की स्थापना की गई, भविष्य मे भारत सरकार के लिए यह ऋण लेने का कार्य करेगा

5. विदेशी मुद्रा भण्डारों का संरक्षण करती है।

   – विदेशी परिसम्पतिया
   – वर्तमान में RBI के पास 371 अरब डॉलर के आस पास विदेशी मुद्रा है।
   – सोना
   – आरक्षित Reserve Tranche (IMF)
   – विशेष आहरण अधिकार (SDR – Special Drawing Rights)

Springboard ACADEMY

6. RBI समय–समय पर बाजार में हस्तक्षेप करती रहती है ताकि रूपए की वित्तीय दर को स्थिर बनाए रख सके। रूपए की विनीमय दर का प्रबंधन करती है।

7. RBI बैंकों को क्लियरिंग हाउस (क्षमा शोधन गृह) की सुविधा उपलब्ध करवाता है।

8. बाजार की तरलता को नियंत्रित करता है।

– RBI तरलता को नियंत्रित करने के लिए दो तरह के उपाय करती है।

i. मात्रात्मक उपाय»

1. बैंक दर (Bank Rate)
2. नकद आरक्षित अनुपात CRR (Cash Reserve Ratio)
3. सांविधानिक तरलता अनुपात SLR (Satutory Liquidity Ratio)
4. रेपो दर (Repo Rate)
5. रिवर्स रेपो दर (Reverse Repo Rate)
6. MSF (Marginal Standing Facility)

ii. गुणात्मक उपाय »

1. Margin Requirement
2. Consumer Credit Regulation
3. Rationing Of Credit
4. Moral Suasion

मात्रात्मक उपाय »

(i) बैंक दर–वह ब्याज दर जिस पर RBI बैंक को लम्बे समय तक के लिए ऋण देता है।

– इसे पिनल रेट भी कहते है क्योंकि जो बैंक CRR व SLR का पालन नहीं करते उन बैंकों से यह ब्याज लिया जाता है।

(ii) नकद आरक्षित अनुपात–सभी बैंकों को अपनी कुलदेयता का एक निश्चित %RBI के पास जमा करवाना होता है।

इस पर RBI कोई ब्याज नहीं देता है। यह 4%है

(iii) सांविधानिक तरलता अनुपात –सभी बैंकों को अपनी देयता का कुछ प्रतिशत तरल परिसम्पतियों के रूप में रखना होता है। जैसे सोना, कैश, शेयर

» भारत में सभी बैंकों को अपनी कुलदेयता का कुछ % SLR सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना अनिवार्य है।

यह 21% है

- LAF (Liqudity Adjusted Facility)

– RBI ने ये सुविधा सन् 2000 में शुरू की ।

– यह बैंकों की अल्पकालिक तरलता संबंधी समस्याओं के लिए शुरू की गई। इसके अन्तर्गत ही रेपो मार्केट को शुरू किया गया।

»Repo Purchase Option

– इसके तहत धन का विक्रेता एक निश्चित अवधि बाद अपने धन को पुनः खरीदने का विकल्प अपने पास रखता है। अपने पास सुरक्षित रखता है।

भारत में रेपो मार्केट के तहत RBI और बैंकों के बीच अल्पकालिक लेन–देन होता है। इसमें सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखी जाती है।

– नरसिंमनहन समिति की सिफारिश पर ये सुविधा शुरू की गई।

(iv) रेपो दर:- वह ब्याज दर जिस पर बैंकों को RBI अल्पकालीक ऋण उपलब्ध करवाती है।

(v) रिवर्स रेपो रेट :– वह ब्याज दर जिस पर बैंक अपना धन RBI को जमा करवाती है।

(vi) MSF (Marginal Standing Facility) :- यह सुविधा RBI में 2000 में शुरू की है इसके तहत बैंक RBI से 1 दिन के लिए ऋण लेते है।

* यदि शुक्रवार को पैसे लिए जाते हो तो तीन दिन बाद ही वापस जमा होगे। इसमें अधिकतम 1 करोड़ रूपए ले सकते है यह CRR को बनाए रखने के लिए किया जाता है।

– और इससे अधिक चाहिए तो भी 1 करोड़ के गुणात्मक होनी चाहिए।

– यह अधिकतम राशि RBI में बैंक की कुल जमाओं (मांग व अवधि जमा) के 2% हो सकती है।

– CRR व SLR को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है

–इसकी ब्याज दर MSF दर कहलाती है

– ये केवल अभी मुम्बई में ही उपलब्ध है।

– 60 दिन के अन्तराल में RBI मौद्रिक निती की समीक्षा करती है। और इस दौरान इन दरों में बदलाव किया जाता है।

– कभी–कभी RBI इन दरों में बीच में ही बदलाव कर देती है तो इसे नितीगत दरें कहते है।

– यदि बाजार में मंदी हो तो RBI इन दरों को घटाती है और यदि बाजार में मुद्रा स्फिती (तरलता) अधिक है तो RBI इन दरों को बढ़ाती है।

- खुले बाजार की क्रियाए- OMO(OPEN MARKET OPERATION):-

बाजार की तरलता को नियंत्रित करने के लिए RBI OMO का प्रयोग करती है। इसके तहत RBI प्रतिभूतियों की बिक्री करती है और आर्थिक मंदी हो तो प्रतिभूतियां खरीदती है।

– यह ब्याज दरों में कमी/या वृद्धि कर खरीद या बिक्री करता है।

–यदि मुद्रास्फीति (महंगाई) की समस्या हो तो प्रतिभूतियों की बिक्री करता है

–यदि आर्थिक मंदी की स्थिति हो तो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है

–मुद्रास्फीति की स्थिति मे RBI इन सभी की दरों मै वर्द्धि करता है

–रेपो मार्किट के तुलना मे ओपन मार्किट की अवधि ज्यादा होती है क्योकि रेपो मार्किट मे प्रतिभूतियों को गिरवी रखा जाता है तथा खुले बाजार क्रिया मै प्रतिभूतियों को खरीदा या बेचा जाता है

– इसलिए ही OMO (ऑपन मार्केट ऑपरेशन) लम्बे समय का टांजेक्शन है।

– गुणात्मक उपाय :–

1. Margine Requirement

2. Consumer Credit Regulation

3. Rationing Of Credit

4. Moral

(i) Margine Requirement**:-**1. इसमें RBI मार्जन मनी को कम या अधिक करता है। यदि मुद्रा स्फीति की समस्या हो तो RBI मार्जन मनी को बढ़ाता है। तथा मंदी की स्थिति में इसे कम करता है।

(ii) Consumer Credit Regulation**:-** इसके तहत अग्रिम भुगतान की राशि को कम या ज्यादा किया जाता है।

(iii) Rationing Of Credit:– इसके तहत RBI विभिन्न क्षेत्रों में दिये जाने वाले क्रेडिट की सीमा तय कर देता है।मुद्रा सफिती की स्थिति में उपभोक्ता लोन कम कर दिये जाते है और निवेशकों को अधिक ऋण दिये जाते है।

(iv) नैतिक दबाव (Moral Suasion):–RBI बैंकों पर नैतिक दबाव उत्पन्न करती है (आर्थिक मंदी की स्थिति मे बैंकों को ऋण देने के लिए प्रेरित करती है और मुद्रास्फीति मे ऋण कम देती है

Priority Sector Lending (PSL) सभी बैंकों को अपनी ऋण योग्य राशि का न्यूनतम 40% प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में देना आवश्यक है।

जैसे कृषि (18%), लघु उद्योग, –STSC, छोटे आवासीय ऋण, छोटे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को ऋण, शिक्षा पर लोन, NBFC-MFI [22% और Sector में]

• कृषि क्षेत्र में 18% देना अनिवार्य है।

- ➢ प्राथमिक ऋण क्षेत्र (Priority Sector Lending) (PSL):-
  - – सभी बैंकों को अपनी ऋण योग्य राशी का कम से कम 40% प्राथमिक क्षेत्र मे देना अनिवार्य है
  - – इसकी अधिकतम ब्याज दर 12%होती है
  - – इसके अंतर्गत निम्न क्षेत्र आते है– कृषि – 18%, लघु उद्योग, नियलिक SC, ST महिलाए , गृह ऋण, छुट्टियों मे रहने वाले लोग, NBFC- MFI.

- ➢ प्राथमिक ऋण क्षेत्र का प्रमाण पत्र (Priority Sector Lending Certificate) (PSLC)

– 7 अप्रैल, 2016 को RBI ने सूचना जारी की जिसमे बैंको को खरीदने या बेचने का प्राथमिक ऋण क्षेत्र का प्रमाण पत्र दिया गया
– जो बैंक अपने लक्ष्य से अधिक प्राथमिक क्षेत्र वाले को ऋण दे सकते है तो इस प्रकार बेच सकते है. जो बैंक अपने प्राथमिक वाले क्षेत्र ऋण नहीं दे सकते तो वह प्रमाण पत्र नहीं बेच सकते.
– कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के तहत यह व्यवस्था शुरू की गई है. चार प्रकार के जारी कर सकता है
  - कृषि के लिए
  - सीमांत किसानो के लिए
  - सूक्ष्म उद्योगों के लिए
  - सामान्य

➢ पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR (Capital Adequacy Ratio)

– सभी बैंकों को अपनी जोखिम युक्त परिसम्पतियों का एक निश्चित प्रतिशत स्वयं की पूंजी का रखना होता है। यह लगभग 10% के बराबर होता हैं।
– उदा. यदि बैंक जोखिम वाले क्षेत्र में 1 करोड़ का ऋण देता हो तो उसमें से 10 लाख रू. खुद की पूंजी होती है।
– उद्देश्य :– जमाकर्ताओं के हितों को संरक्षण देना ।
– यदि बैंक अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में ऋण देता है तो उसे उसमें अपनी पूंजी का प्रतिशत बढ़ाना होता है।

CAR की अवधारणा बसेल से अपनाया है

➢ Bank For International Settlement
  - BIS की स्थापना 1930 में की गई।
  - यह केन्द्रिय बैंकों का संगठन है।
  - इनका हेडक्वार्टर स्विटजरलैण्ड के बॅसल क्षेत्र में है।

– उद्देश्य :– बैंकिंग क्षेत्र का विकास
  - यह बैंकिंग क्षेत्र के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। (विकास हेतु)
  - BIS के इन्हीं दिशा निर्देशों को बेसल मानक कहते है।
  - अनुसन्धान को प्रोत्साहन देता है

– अभी तक तीन बेसल-I,बेसल- II, बेसल-III मानक जारी किये गये है।
– बेसल थर्ड – 2013–14 के बीच भारत को बेसल मानकों को लागू करने का समय बैंकों को दिया गया है।
– 1996 में RBI इसका सदस्य बना।

➢ कॉल–मनी बाजार (Call Money Market):-

– रोजमर्रा के लेनदेन के दौरान कुछ बैंकों के पास धन की कमी हो जाती है। जबकि कुछ बैंकों के पास धन अधिक होता है तो इस तरह बैंकों के बीच आपसी लेनदेन होता है जिसे ''कॉल मनी मार्केट'' कहते है।
– यह अति अल्पकालिक बाजार है इसकी अधिकतम अवधि 14 दिन होती है।
– लेकिन इसमें प्रायः एक दिन के लिए दिया जाता है इसकी ब्याज दर ''कॉलरेट'' कहलाती है। इसमें उतार चढ़ाव बहुत अधिक होते है।
– यह बाजार की तरलता की स्थिति को दर्शाता है।
– और इसलिए केन्द्रिय बैंक मौद्रिक निती के निर्धारण में इसका संदर्भ लेती है। इसलिए इसे संदर्भ या reference Rate कहते है।

– विश्व का सबसे बड़ा कॉल मनी मार्केट लन्दन है। जहां की कॉलरेट LIBOR (London Inter Bank Offer Rate) कहलाती है।
– LIBOR की गणना BBA (ब्रिटिश बैंक एसोसिएशन)करता है ।
– 2012 ई.मे LIBOR घोटाला हुआ था
– भारत का Call Money Market मुम्बई में है। इसे MIBOR कहते है।

➢ बैंकिग लोकपाल (Banking Ombudsman) :– 1995 में RBI नें देश में 15 बैकिंग लोकपाल (वित्तीय) विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त किये।
– ये ग्राहकों की बैंक के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई करता है ।

* जयपुर में भी शुरू किया गया।

यह निम्न बैंकों की शिकायतें सुन सकता है –

1. अनुसूचित बैंक
2. कोपरेटिव बैंक
3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
4. NBFC (केवल फाइनेंस के लिए)

– शिकायतों का प्रकार :–

1. यदि कोई छुपे हुए चार्ज लगाता है तो ।
2. समय–समय पर चैक क्लियर नहीं होते है।
3. योग्यता के बावजूद बैंक लोन देने को मना कर देता है।
4. बैंक खाता खोलने से बिल्कुल मना कर देता है।
5. सिक्के लेने से इन्कार कर दे।
6. अकाउंट को बंद नहीं करना

जो शिकायतें नहीं की जा सकती :–

1. एक साल पुराने मामलो की शिकायत नही की जा सकती ।
2. 10 लाख से अधिक के मामले में यहां शिकायत नहीं हो सकती है।
3. वह समस्या जिसकी सुनवायी DRT के द्वारा हो रही हो।
4. सामान्य शिकायतें आदि।

कोई भी शिकायत हो तो सवर्प्रथम रूप से बैंक मेनेजर को करनी चाहिए. यदि वह समाधान नही करता है तो शिकायत कर सकते है ।

– बैंकिंग लोकपाल के शिकायत RBI के उपगर्वनर के पास की जाती है।

– बैकिंग लोकपाल 1 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है।

Springboard ACADEMY

– नेट बैकिंग की शिकायत भी की जा सकती है।

– ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है।

– प्रत्येक बैंक की ब्रांच को अनिवार्य है कि वो बैंकिंग लोकपाल का विज्ञापन लगाए।

➢ <u>नरसिंमहन कमेटी (1) 1992</u>

1. बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिए।
2. विदेशी बैंकों को भारत में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
3. विदेशी व घरेलू बैंकों में भेदभाव नहीं किये जाने चाहिए।
4. निजी क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
5. CRR, SLR को कम किया जाना चाहिए।
6. क्रेडिट इनफोरमेशन ब्यूरो की स्थापना की जानी चाहिए।
7. DRT (ऋण वसूली न्यायाधिकरण) की स्थापना की जानी चाहिए।
8. ARC (Asset Reconstruction Company) की स्थापना की जानी चाहिए।
9. सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को 51% कर देनी चाहिए।
10. सन् 2000 CIBIL स्थापना की गई।

<u>नरसिहम्न कमेटी (2) 1998 –</u>

– बैंकों के आपसी विलय को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ताकि वो विदेशी बैंकों से प्रतिर्स्पधा कर सकें।

– कमजोर बैंकों का विलय मजबूत बैंकों में नहीं किया जाना चाहिए।

– सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को 51% से कम करके 33% कर देनी चाहिए।

– बेसल मानकों को लागू किया जाना चाहिए।

–कमजोर बैंकों को नैरो बैंकिंग के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए

(नैरो बैंक – जोखिम क्षेत्र मे निवेश नहीं करने वाला बैंक)

–CAR को लागू किया जाना चाहिए।

–NBFC को भी RBI के दायरे में लाना चाहिए।

– बैंकों को कम्प्यूटरीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

Springboard ACADEMY